नहीं रहेगा एपीएल बीपीएल का भेद

अमल में खोट के कारण नहीं मिलते योजनाओं के नतीजे

भोपाल(नप्र)। 12वीं पंचवर्षीय योजना में सभी सरकारी योजनाओं से एपीएल और बीपीएल का भेद खत्म किया जा रहा है। योजनाओं का लाभ लेने के लिए इसे आधार नहीं माना जाएगा। इससे वास्तविक पात्र लोगों को लाभ मिल सकेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए हर राज्य में एक सोशल ऑडिट डायरेक्टोरेट बनाया जाएगा और योजना आयोग में इसके लिए एक स्वतंत्र मूल्यांकन ऑफिस भी बनेगा।

यह बात आयोग के सदस्य मिहिर शाह ने गुरुवार को यहां विकेंद्रीकृत नियोजन पर आधारित कार्यशाला में कही। सेंटर फॉर स्टडीज ऑफ डेवलपिंग सोसायटीज (सीएसडीएस) नई दिल्ली द्वारा संचालित इंक्लूसिव मीडिया फॉर चेंज ने यह दो दिवसीय मीडिया कार्यशाला यूएनडीपी के सहयोग से आयोजित की है। मीडिया के लोगों को विकेंद्रीकृत योजनाओं के प्रति संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यशाला में विशेषज्ञों ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन का तरीका बदलने की जरूरत है। मीडिया को भी इस विकेंद्रीकृत व्यवस्था के प्रति संवेदनशील बनना होगा।

मीडिया कार्यशाला में हुआ विकेन्द्रीकृत नियोजन पर मंथन

उद्घाटन सत्र को वित्त मंत्री राघवजी, राज्य योजना आयोग के सदस्य सचिव एसआर मोहंती, आयोग के सलाहकार मंगेश त्यागी और यूएनडीपी की डिप्टी कंट्री डायरेक्टर अलेक्जेंड्रा सोलोविवा ने भी संबोधित किया।

राष्ट्रीय सलाहकार परिषद के सदस्य डॉ. मिहिर शाह ने कहा कि योजनाओं पर खर्च की गई राशि और उनके परिणामों में बहुत बड़ा अंतर है। योजना के तीन महत्वपूर्ण घटक हैं- नीति निर्धारण, योजना निर्माण और क्रियान्वयन। पहले दो काम तो ठीक हो रहे हैं लेकिन क्रियान्वयन में कमी है। क्रियान्वयन की बारीकियां जब तक नीति निर्धारकों को पता नहीं चलती तब तक अच्छी नीतियां नहीं बन सकती। आम आदमी का योजनाओं जुड़ना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम में मप्र योजना आयोग के उपाध्यक्ष बाबूलाल जैन भी उपस्थित रहे।

ग्रामीण बनाएं योजना, सरकार दे फंड

कार्यशाला के तकनीकी सत्र की अध्यक्षता करते हुए नईदुनिया समूह के प्रधान संपादक श्रवण गर्ग ने कहा कि यह बहस का विषय है कि योजना बनाने की जिम्मेदारी सरकार को दी जाए या उसे आउटसोर्स किया जाए। होना तो यह चाहिए कि ग्रामीण अपनी योजना बनाएं और सरकार सिर्फ फंडिंग एजेंसी की तरह काम करे। आज मीडिया में केन्द्रीकरण बढ़ रहा है इसलिए उसके दिमाग में विकेन्द्रीकरण की बातें नहीं आती। इसके लिए माइंड सैट को बदलने की जरूरत है। मीडिया अपना काम ईमानदारी से कर रहा है लेकिन पाठकों की तरफ से डिमांड भी जनरेट होनी चाहिए। सत्र की अध्यक्षता हिन्दुस्तान टाइम्स भोपाल के स्थानीय संपादक द्वैपायन बोस ने की।

प्लानिंग हो व्यावहारिक

वित्त मंत्री राघवजी ने कहा कि मध्यप्रदेश में विकेन्द्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हर गांव का मास्टर प्लान बनाया गया है। विकेंद्रीकृत प्लानिंग यदि व्यावहारिक हो तो उससे समाज का असंतुलन दूर होगा।

पूरा फंड केन्द्र के कब्जे में

यूएनडीपी के वरिष्ठ सलाहकार टीआर रघुनंदन ने कहा कि भारत में विकेन्द्रीकरण की बातें तो बहुत होती हैं लेकिन दरअसल केन्द्रीकरण ही बढ़ रहा है। पूरा फंड केन्द्र के कब्जे में रहता है और वह अपनी मर्जी से इसे रिलीज करता है। फंड ट्रांसफर में गड़बड़ियों के कारण ही काम ठीक से नहीं हो पा रहे। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के सदस्य विनोद रैना ने कहा कि विकेन्द्रीकरण के लिए जितने स्तर हैं सभी को पॉवर भी दिए जाएं।

विकेन्द्रीकृत नियोजन जरूरी

इंक्लूसिव मीडिया फॉर चेंज के डायरेक्टर डॉ. विपुल मुद्गल ने कहा कि सकारात्मक बदलाव के लिए निचले स्तर पर नियोजन और संसाधनों का तालमेल जरूरी है। विकेन्द्रीकृत नियोजन के बिना इसे पाना मुश्किल है। सोशल ऑडिट को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हालांकि मीडिया की सीमाएं हैं लेकिन विकास की खबरें रुचिकर ढंग से लिखी जाएं तो उन्हें स्थान जरूर मिलेगा।